स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–10, आश्विन–कार्तिक 2068, अक्टूबर 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

सरकार यह कहती है कि 32 रूपये प्रतिदिन खाना, इलाज और अन्य मद में खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर माना चाहिए तो यह क्रूर मजाक ही है।

अनुक्रम

आवरण लेख
गरीबी का निर्धारण या गरीबों का मजाक
– विक्रम उपाध्याय / 4

कृषि
फिर खेती में मंडराया संकट
– देविन्दर शर्मा / 7

वाद–विवाद
32 रुपए में कैसे जिएगा आम आदमी
– राजेश सिंह / 10

गरीबी
गरीबों के साथ क्रूर मजाक
– गिरीश अवस्थी / 13

दृष्टिकोण
आर्थिक चुनौतियों से कैसे निपटेगा भारत
– डॉ. अश्विनी महाजन / 16

अर्थव्यवस्था
यूरोप के संकट का आधार
– डॉ. भरत झुनझुनवाला / 19

मुद्दा
निर्यात की डगर पर बढ़ती मुश्किलें
– जयंतीलाल भंडारी / 22

पर्यावरण
नदियों के प्रवाह की रक्षा
– भारत डोगरा / 25

अंतर्राष्ट्रीय
पानी के लिए दादागिरी
– उमेश प्रसाद सिंह / 27

भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती संप्रग सरकार
– बलवीर पुंज / 29

पड़ताल
रामदेव व अन्ना के आंदोलन के बाद कांग्रेस
– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल / 31

पाठकनामा / 2, रपट / 34, आन्दोलन / 36

पाठकनामा

किसानों को नहीं मिलता अपनी उपज का उचित मूल्य

'जय जवान जय किसान' का नारा जब लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तब जवानों ने भारत की रक्षा और किसानों ने खेती द्वारा भारत की जनता को भरपूर अनाज दिया था। परंतु आज के हालात देखा जाए तो जवानों को सरकार द्वारा काफी कुछ मिलता है लेकिन किसानों को दो वक्त की रोटी खाना भी दूभर हो गया है। कारण खेती आज किसानों के लिए 'जी का जंजाल' बन गई है। अगर खेती नहीं करते तो एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। कारण देश में आज लगातार खेती के संसाधनों की कीमत दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है लेकिन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। दूसरी ओर महंगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और बिचौलिए और दलाल इस महंगाई का भरपूर फायदा उठा रहे है। इसमें प्रशासनिक तंत्र के अधिकारियों की भी मिली भगत है। किसान अपने खेतों को बेच रहे है। खेत वाली जमीन पर अवैध निर्माण और बिल्डरों द्वारा फ्लैट बनाने की प्रक्रिया आज पूरे भारत में चल रही है। सोचने वाली बात है अगर इसी तरह घरों की संख्या बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब खेती करने के लिए कोई जमीन ही नहीं बचेगी। आज से दस साल पहले दिल्ली से सटे इलाकों में खेती होती थी। इन इलाकों में आज शानदार फ्लैटों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इंदिरापुरम से लेकर मेरठ तक अवैध निर्माण और बिल्डरों का कब्जा हो चुका है। कारण स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार किसानों का कोई हित ही नहीं चाहती। जिसके कारण किसान अपने खेत बेच रहे हैं। अगर सरकार ने जल्दी इस पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले वक्त में भारत को अनाज भी विदेशों से आयात करना पड़ेगा। साथ ही 'जय जवान जय किसान' के नारे से किसान गायब ही हो जाएगा।

— राकेश कुमार मीडिया अपार्टमेंट, गाजियाबाद

लुप्त होती खेती और जंगल

भारत भविष्य में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा! क्या हम इसके लिए तैयार हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं!! आज भारत की आबादी 121 करोड़ के पार हो चुकी है। इतने लोगों को रहने के लिए जगह, खाने के लिए खेती और पानी ये सभी चीजें हमें इस धरती से ही मिलती है। लेकिन हमारे पास इतनी जमीन कहां बची है? कभी किसी ने सोचा। मेरा गाँव ज्यादा बड़ा नहीं है। पहले जहां गांव के चारों तरफ खेती होती थी और दूसरी तरफ जंगल होता था। उस जंगल में जगली पशु भी रहते थे, परंतु आज जंगल और खेती दोनों ही धीरे–धीरे गायब होते जा रहे हैं। खेती वाली जगह पर कारखाने और बिल्डिंग बन रही है जिसके कारण जंगल भी धीरे–धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। जब मेरे गांव का यह हाल है तो हमारे देश में अन्य जगह भी यही सब चल रहा है। मनुष्य का स्वाभाविक रूप है कि वह लोभी होता है। लेकिन अपने लोभ के कारण वह पेड़–पौधों, वनस्पति और पशु–पक्षियों को नष्ट कर रहा है। अगर हमने लोभ नहीं छोड़ तो आने वाले वक्त में कैसे महाशक्ति बन पाएंगे। जब अनाज और खुली हवा नहीं मिलेगी तो कैसे हम जी पाएंगे। — **प्रणय अशोकराव साखकर**, क्वाटर नं. एम–23/5, घोषताल टाउनशिप, पोस्ट – सास्ती, तहसील – राजुरा, जिला – चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

मुझे महात्मा कहना गलत है। महात्मा का ओहदा बहुत बड़ा है और मैं इस लायक नहीं हूँ।

— अन्ना हजारे

32 रुपये रोजाना पर केवल जानवर ही जी सकते हैं। देश में 80 प्रतिशत आबादी गरीब है। सरकार को उन्हें लाभ पहुंचाना चाहिए। 32 रुपये रोजाना खर्च करने वाले अमानवीय हालात में जीते हैं।

— एन.सी. सक्सेना

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य

वर्तमान आर्थिक नीतियों में सुधार किया जाए और काला धन वापस लाया जाए तो देश फिर से बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा।

— रामदेव बाबा

संपादकीय

मितव्ययता का नाटक

प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के विदेश दौरे पर रोक लगा दी है। ऐसा उन्होंने आर्थिक मंदी के खतरे को देखते हुए किया है। यह खबर जनता को इसलिए दी गई ताकि सरकार यह संदेश दे सके कि वह मितव्ययता से काम कर रही है। फालतू के खर्चे में जबर्दस्त कटौती कर रही है। प्रधानमंत्री संभवतः यह सोंच रहे होंगे कि उनके इस कदम से जनता मानसिक रूप से राहत महसूस करेगी कि सरकार वाकई उनकी तकलीफों से चिंतित है और उनसे उबरने के प्रयास में लगी हुई है। आम आदमी ऐसा सोंचता भी यदि एक सप्ताह पहले ही उसके पास यह खबर नहीं होती कि यूपीए सरकार के मंत्रियों ने पिछले एक साल में अपने विदेशी दौर पर 42 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हवाई जहाज से लेकर होटलों के खर्चे बेहिसाब हुए। इससे देश को क्या हासिल हुआ, जनता को क्या मिला प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले मंत्रियों के विदेश दौरे नहीं हुए पहले की सरकारों ने इस मद में कोई खर्च नहीं किए। पर पहली बार ऐसा हुआ कि मनमोहन सिंह के मंत्रियों में विदेश दौरे के लेकर होड़ देखी गई। खासकर कमलनाथ और प्रफुल्ल पटेल जैसे मंत्रियों ने विदेश दौरे का नया रिकार्ड बनाया। कानून मंत्री से लेकर गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत के मंत्री तक विदेश भागते रहे। सरकार की ही सूचनाओं के अनुसार कमलनाथ ने विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा से भी ज्यादा बार विलायत की यात्रा की। कमलनाथ का विदेश प्रेम किसी की भी समझ से परे है। प्रधानमंत्री को कई बार कमलनाथ की यात्राओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ी है। यूपीए सरकार के मंत्रियों का विदेशी दौरा कई बार कुछ गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। कम से कम आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो बार–बार निजी खर्चे पर भी विदेशों की खूब यात्रा करते हैं। यूपीए सरकार के मंत्रियों के लिये दुबई सबसे पसंदीदा जगह है। लगभग एक दर्जन मंत्री दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य शहरों में आते–जाते रहते हैं। अब सबको मालूम है कि दुबई किस चीज के लिये जाना जाता है। दुनिया के तमाम रईसजादे या तो वहां मस्ती के लिये जाते हैं या फिर दुबई धन को ठिकाने लगाने का कुख्यात ठिकाना है। हमारे यह कहना कतई नहीं है कि हमारे मंत्री भी मौज–मस्ती या निवेश के लिये दुबई जाते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि बार–बार दुबई जाने का मकसद राष्ट्रीय हित या जनता के दुःख को कम करने का प्रयास नहीं हो सकता। बहरहाल प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए और यह माना जाना चाहिए कि देर आये दुरूस्त आये। क्योंकि मंत्रियों के देश में न होने के कारण और नीतियों पर उनकी कहीं पकड़ न होने के कारण जनता गंभीर परिणाम भुगत रही है। लगभग सभी प्रमुख मंत्रालयों में कामकाज जैसे–तैसे चल रहा है। अभी हाल ही में एक खबर आई कि कम से कम आधा मंत्रालयों में सचिव का पद खाली है यानि ये मंत्रालय अपने कामकाज को सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। सरकार की खामियों का भुगतान जनता कर रही है। लगातार कई साल अच्छे मानसून होने के बावजूद किसानों की जीतोड़ मेहनत के बावजूद, अच्छी उपज हासिल होने के बावजूद भी महंगाई कम नहीं हो रही है। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार भी दम तोड़ रहे हैं। उनका असर भी कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे में सरकार के मंत्रियों का सैर–सपाटा और कामकाज के प्रति लापरवाही देश के लिये बहुत भारी पड़ेगी। अब यह कहने का समय समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री मनमोहन बहुत ईमानदार व स्पष्ट छवि के हैं। वे एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं और अर्थव्यवस्था की नब्ज पर उनकी अच्छी पकड़ है। प्रधानमंत्री के सभी गुणों का प्रभाव देश की राजनीति पर नहीं पड़ा है। उनकी ईमानदार छवि के बावजूद भी उनके मंत्रिमंडल के लोग घोटाले करते रहे। उनके अर्थशास्त्री होने के बावजूद देश भयंकर महंगाई की चपेट में है। अर्थव्यवस्था पर कथित रूप से उनकी पकड़ होने के बावजूद हम फिर आर्थिक मंदी की तरफ धकेले जा रहे हैं। अब देखें उनके मितव्ययी होने का फायदा देश को किस रूप में पहुंचता है। जनता तो अपनी गाढ़ी कमाई दाल–रोटी के गुजारे में ही लुटा रही है। जीवन इतना कठिन हो गया है कि एक अच्छा–खासा कमाने वाला व्यक्ति भी त्राहि–त्राहि कर रहा है। त्रासदी यह है कि मनमोहन जैसे प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत पता नहीं है। इसीलिये कई बार सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सरकार जिम्मेदारी से काम करने के बजाय बड़ी–बड़ी समस्याओं पर भी गैर जिम्मेदारी से पेश आती है। सरकार में शामिल कुछ लोग अपनी बयानबाजी के कारण भी सरकार की किरकिरी कराते रहते हैं। खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि के मामले में शरद पवार के बयान से कई बार सरकार किनारा कर चुकी है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी सरकार की किरकिरी का कारण बन रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जनता की जख्मों पर एक और चोट किया, जब उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि देश के लिये अच्छा है। हद तो तब हो गयी जब मोंटेक सिंह ने यह कहा कि 32 रूपए रोजाना कमाने वाले लोग गरीबों की श्रेणी में नहीं आ सकते। काफी तू–तू मैं–मैं और थू–थू के बाद प्रधानमंत्री को गरीबों की पहचान के लिये नये मापदंड बनाने पड़े। अब देखें प्रधानमंत्री के नये प्रयास का क्या असर होता है।

गरीबी का निर्धारण या गरीबों का मजाक

सरकार यह कहती है कि 32 रूपये प्रतिदिन खाना, इलाज और अन्य मद में खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर माना चाहिए तो यह क्रूर मजाक ही है। जी हां, केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथपत्र के जरिये यह बयान दिया कि उसकी नजर में 32 रूपये खर्च करने वाले लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं और उन्हें सामाजिक कल्याण के लिये दी जाने वाली सब्सिडी के लिये उपयुक्त नहीं माना जाना चाहिए।

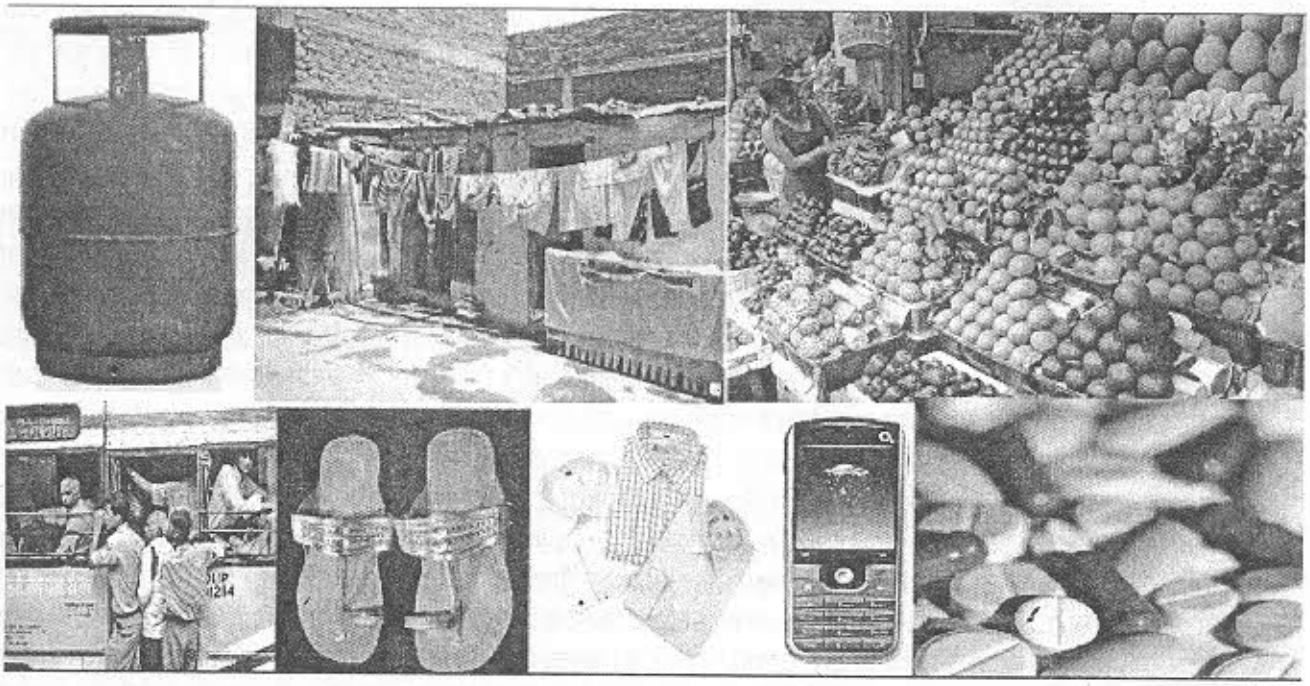

■ विक्रम उपाध्याय

सरकार हकीकत से मुंह मोड़ रही है। अपनी कमजोरियों और अक्षमताओं को जनता पर थोप रही है। योजना आयोग भी सरकार को अंधेरे में रखकर उलट पुलट सलाह दे रहा है। यह डर दिखाया जा रहा है कि सरकार सामाजिक कल्याण और रोजगार के लिये अब और धन खर्च करने की कोशिश करती है तो अर्थव्यवस्था चरमरा जायेगा जबकि भारत जैसे देश में सामाजिक कल्याण रोजगार पर आने वाले खर्च अकेले ही केन्द्र सरकार वहन नहीं करती।

देश की आबादी यदि 120 करोड़ है तो गरीबों की संख्या 60 करोड़ से ऊपर है। भले ही आंकड़ा किसी सरकारी किताब में नहीं मिलता। सरकार तो 32 करोड़ से लेकर 40 करोड़ लोगों को ही गरीबी रेखा से नीचे मान रही है। लेकिन दैनिक खर्चे और आमदनी के बीच यदि आंकलन करें तो यह आंकड़ा बिल्कुल सही दिखता है।

इसमें कोई शक नहीं कि भारत के केवल 12 फीसदी लोग ही कथित रूप से अमीरों की श्रेणी में आते हैं। शेष जनता मध्यम आय वर्ग, निम्न मध्यम आय वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित है। इसमें भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आंकड़े अलग–अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 98 फीसदी लोग निम्न मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग में ही आते हैं।

यदि भारत की कुल जनसंख्या का 60 फीसदी हिस्सा भी ग्रामीण आबादी का मानें तो यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गरीबी की जिंदगी जीने वालों की आबादी कुल आबादी का 70 फीसदी से कम नहीं है। ऐसे में यदि कोई सरकार यह कहती है कि 32 रूपये प्रतिदिन खाना, इलाज और अन्य मद में खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से

ऊपर माना चाहिए तो यह क्रूर मजाक ही है। जी हां, केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथपत्र के जरिये यह बयान दिया कि उसकी नजर में 32 रूपये खर्च करने वाले लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं और उन्हें सामाजिक कल्याण के लिये दी जाने वाली सब्सिडी के लिये उपयुक्त नहीं माना जाना चाहिए।

हालांकि इस मसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने आनन–फानन में गरीबी निर्धारण के नये मापदंड गढ़ दिये। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला और योजना आयोग के साथ बैठकर इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया ताकि सरकार की और किरकिरी न हो लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफ़नामे ने देश में एक नई बहस नींव रख दी है, जिसमें इस बात पर ज्यादा चर्चा हो रही है कि गरीब किसे मानें। सरकार की नीतियों ने लगभग 10 करोड़ नये लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ला पटका है।

2004–05 के आंकड़े के अनुसार 10 करोड़ नये लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट इस बात पर मुहर लगाती है।

शहरी क्षेत्रों में 32 रूपये नहीं, 200 रूपये प्रतिदिन कमाने वाले भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। योजना

आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि उसके आंकलन का आधार यह था कि अमूमन एक परिवार में 5 या 6 लोग होते हैं और 32 रूपये प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति पर खर्च का अर्थ होता है लगभग 6000 रूपये प्रतिमाह की आमदनी।

एक तरह से देखें तो एक व्यक्ति जिसकी मासिक आमदनी 6000 रूपये महीने है उसे सैद्धान्तिक रूप से गरीबी रेखा के नीचे नहीं मान सकते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ठीक इसके उलट है। आज भी प्रत्येक कमाने वाले व्यक्ति पर लगभग 5 लोग आश्रित हैं। इन सभी के भरण–पोषण की जिम्मेदारी कमाने वाले व्यक्ति पर ही होती है। यदि 6000 रूपये प्रतिमाह के आधार पर ही खर्चे का आंकलन करें तो एक परिवार मुश्किल से 10 दिन के खर्चे चला सकता है। लेकिन उसे पूरे 30 दिन उसी में गुजारा करना पड़ता है। पोषक तत्वों की बात छोड़े, आहार में उसे रोटी–नमक ही मिल जाये उसके लिये बहुत होता है। उसे भोजन में मिलने वाले कैलोरी की चिंता नहीं पेट भरने की चिंता रहती है। सरकार इससे वाकिफ है फिर भी इस तरह के हलफनामे कोर्ट में दाखिल किये जा रहे हैं तो उसका मकसद क्या है।

दरअसल कांग्रेस अपने ही खेल में

सरकार ने आनन–फानन में गरीबी निर्धारण के नये मापदंड गढ़ दिये। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला और योजना आयोग के साथ बैठकर इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया ताकि सरकार की और किरकिरी न हो लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफ़नामे ने देश में एक नई बहस नींव रख दी है, जिसमें इस बात पर ज्यादा चर्चा हो रही है कि गरीब किसे मानें। सरकार की नीतियों ने लगभग 10 करोड़ नये लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ला पटका है।